

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2 रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi-110001



सां/No.: 5-1(22)/2008-PD

दिनांक/Dated: 26.10.2018

प्रेषक / From:

संयुक्त सचिव (प्रशासन)
Joint Secretary (Admn.)

सेवा में / To :

सी.एस.आई.आर के सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालों/संस्थाओं/इकाईयों के निदेशक/प्रमुख
The Directors/Heads of all National Labs./Instts./Units of CSIR

महोदय/Sir / महोदया/Madam,

मुझे, जम्मू-कश्मीर निवासी (केंद्रीय सिविल सेवाओं और पदों पर भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट) नियम, 2018 के संबंध में भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, डीओपीटी के 09.02.2018 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 154 (अ) को जानकारी, मार्गदर्शन और अनुपालन के लिए अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।

I am directed to forward herewith Govt. of India, MoPPG&P, DoPT Notification No. G.S.R. 154 (E) dated 09.02.2018 regarding the Residents of the state of Jammu and Kashmir (Relaxation of Upper age limit for Recruitment to Central Civil Services and Posts) Amendment Rules, 2018 for information, guidance and compliance.

भवदीय/Yours faithfully,

(सिद्धार्थ दे /Siddhartha Dey)
अनु. अधि. (नीति प्रभाग) / SO(PD)

संलग्न/Encl. :यथोपरि/As above

प्रतिलिपि/Copy to:

- 1) प्रमुख, आईटी डिवीजन - इस सर्कुलर पत्र को वेबसाइट और नीति रिपोजिटरी पर उपलब्ध कराने के अनुरोध के साथ / Head, IT Division with the request to make this circular letter available on the website & Policy Repository.
- 2) कार्यालय प्रति/Office copy

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th February, 2018

G.S.R. 154(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution and in supersession of the Residents of the State of Jammu and Kashmir (Relaxation of Upper Age Limit for Recruitment to Central Civil Services and Posts) Rules, 1997, except as respects things done or omitted to be done before such supersession and after consultation with the Comptroller and Auditor General of India in relation to the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules regulating the relaxation of age limit in favour of the Residents of the State of Jammu and Kashmir for appointment to Central Civil Services and Posts, namely:—

1. Short title and commencement .-

- (1) These rules may be called the Residents of the State of Jammu and Kashmir (Relaxation of Upper Age Limit for Recruitment to Central Civil Services and Posts) Rules, 2018.
- (2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 2018.

2. Application .-

These rules shall apply to all Central Civil Services and Posts recruitment to which are made through the Union Public Service Commission or the Staff Selection Commission or otherwise by the Central Government.

3. Relaxation of upper age limit .-

Wherever any recruitment to the services and posts referred to in rule 2 is made, a relaxation in the upper age limit of five years shall be admissible to all persons who had ordinarily been domiciled in the State of Jammu and Kashmir during the period from the 1st day of January, 1980 to the 31st day of December, 1989;

Provided that the relaxation in the upper age limit for appearing at any examination shall be subject to the maximum number of chances permissible under the relevant rules.

4. Certificate regarding proof of residence :-

Any person intending to avail of the relaxation of age-limit admissible under rule 3 shall submit a certificate from :-

- (a) the District Magistrate within whose jurisdiction he had ordinarily resided; or
- (b) any other authority designated in this behalf by the Government of Jammu and Kashmir,

to the effect that he had ordinarily been domiciled in the State of Jammu and Kashmir during the period from the 1st day of January, 1980 to the 31st day of December, 1989.

5. Interpretation :-

If any question arises as to the interpretation of these rules the same shall be decided by the Central Government.

6. Amendment of recruitment rules :-

All rules regulating the recruitment of persons to Central Civil Services and Posts including those in the Indian Audit and Accounts Department and the rules governing competitive examinations therefor shall be deemed to have been amended to the extent provided for in these rules.

7. Limitation :-

These rules shall remain in force till the 31st day of December, 2019 and there shall be no further extension beyond the said period.

[F. No. 15012/1/2014-Est.(D)]

GYANENDRA DEV TRIPATHI Jt. Secy.

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Central Government has decided to extend the age relaxation to all persons who had ordinarily been domiciled in the State of Jammu and Kashmir during the period from the 1st day of January, 1980 to the 31st day of December, 1989 for a period of two years to be effective from the 1st January, 2018.

It is clarified that the interest of no person shall be adversely affected by issuing these rules with retrospective effect.

RAKESH
SUKUL

Digitally signed by
RAKESH SUKUL
Date: 2018.02.09
23:52:32 +05:30

Copy to:

1. All Ministries/Departments of the Govt. of India
2. All State Govts./Union Territories.
3. C&AG
4. UPSC
5. SSC.
6. Lok Sabha Secretariat.
7. Rajya Sabha Secretariat
8. Secretary, National Council (JCM)
9. All attached and sub-ordinate offices of DOP.
10. All Sections
11. 300 spare copies for Estt.(D)
12. Chief Secretary, Govt. of J&K
13. Principal Information Officer, Ministry of I&B.
14. Secretary, Department of J&K.
15. Ministry of Railways/Department of Banking/Department of Public Enterprises/Department of Atomic Energy/Department of Space/Department of Electronics/Department of Non- Conventional Energy Sources to issue similar orders for appointment to posts under their control/Nationalised Banks/Public Sector Undertakings.


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 75]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 9, 2018/चैत्र 20, 1939

No. 75]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 9, 2018/MAGHA 20, 1939

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन ब्यूरो

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2018

सा.का.नि. 154(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परमूखी भाग अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए और जम्मू-कश्मीर निवासी (केंद्रीय सिविल सेवाओं और पदों पर भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट) नियम, 1997 को, उन शर्तों के सिवाय जिनको संसद अधिसूचना में पूर्व किया गया है या जिनके अन्तर्गत वे लोग किये जा सकते हैं, अधिक्रान्त करने हुए, और भारतीय सेवा परीक्षा और सेवा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में भारत में महासूचना नियंत्रक और परीक्षक के परामर्श से, केंद्रीय सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्ति के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य के निवासियों को भारत में आयु सीमा को शिथिल करने का विनिश्चय करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने से, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और आरंभ—

(1) इस नियमों का संक्षिप्त नाम जम्मू-कश्मीर निवासी (केंद्रीय सिविल सेवाओं और पदों पर भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट) नियम, 2018 है।

(2) ये 1 जनवरी, 2018 का प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. लागू होना—

ये नियम सभी केंद्रीय सिविल सेवाओं और पदों को लागू होंगे, जिनके भर्ती केंद्रीय सरकार द्वारा संघ लोक सेवा आयोग या कर्माचारि चयन आयोग या अन्यथा के माध्यम से की जाती है।

3. ऊपरी आयु सीमा में छूट—

इस नियम 2 में निर्दिष्ट सेवाओं और पदों के लिए भर्ती की जाएगी। इन सभी व्यक्तियों को, जो साधारणतया जम्मू-कश्मीर राज्य में 1 जनवरी, 1980 से 31 दिसंबर, 1989 के बीच अधिवासा कर रहे थे, ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट अनुज्ञेय होगी।

परंतु भर्ती परीक्षा में भाग लेने के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट प्राप्त करनेवालों के अधीन अनुज्ञेय अधिकतम अवसर की संख्या की शर्त के अधीन होगी।

1. निवास के सबूत के संबंध में प्रमाणपत्र—

नियम 3 के अधीन अनुज्ञेय आयुसीमा में छूट का लाभ लेने की बांछा रखने वाला व्यक्ति निम्नलिखित से इस प्रभाव का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा कि वह 1 जनवरी, 1980 से 31 दिसंबर, 1989 की अवधि के दौरान जम्मू-कश्मीर राज्य में अधिवास कर रहा था—

- (क) जिला मजिस्ट्रेट, जिसकी अधिकारिता में वह साधारणतया निवास कर रहा था ; या
(ख) जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा इस निमित्त पदाभिहित कोई अन्य प्राधिकारी ।

5. निर्वचन—

यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो उसका विनिश्चय केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा ।

6. शर्ती नियमों का संशोधन—

केंद्रीय सिविल सेवाओं और पदों, जिसके अंतर्गत भारतीय सेवा परीक्षा और सेवा विभाग के पद हैं, में व्यक्तियों की शर्ती को विनियमित करने वाले सभी नियम और उनके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का शासन करने वाले नियम, इन नियमों में उपबंधित सीमा तक संशोधित हो गए समझे जाएंगे ।

7. निबन्धन—

ये नियम 31 दिसंबर, 2019 तक प्रवृत्त रहेंगे और उक्त अवधि के पुरे कोई और विस्तार नहीं किया जाएगा ।

[फा. सं. 15012/1/2014-स्था. (व)]

जानेन्द्र देव त्रिपाठी, संयुक्त सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन

केंद्रीय सरकार ने उन सभी व्यक्तियों को, जो 1 जनवरी, 1980 से 31 दिसंबर, 1989 की अवधि के दौरान जम्मू-कश्मीर राज्य में साधारणतया अधिवास कर रहे थे, 1 जनवरी, 2018 से प्रभावी होने वाली दो वर्ष की अवधि के लिए आयु सीमा में छूट देने का विनिश्चय किया है ।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इन नियमों को भूतलक्षी-प्रभाव देने में किसी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।